

भारत-अमेरिकी निवेश में आएगी मजबूती

भारत में निवेश बढ़ाने, एआई, डिजिटल भुगतान और विनिर्माण क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया

नयी दिल्ली, 29 मई. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान कई उच्च स्तरीय व्यापार और निवेश संबंधी बैठकों में शामिल हुए जिनका मुख्य उद्देश्य भारत-अमेरिका व्यापार और निवेश संबंध को मजबूत करना था।



वाणिज्य मंत्रालय की शुरुआत को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार श्री गोयल कनाडा की अपनी तीन दिन की यात्रा समाप्त कर 28 मई को न्यूयॉर्क पहुंचे। श्री गोयल ने न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान कालाहिल ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हार्वे श्वार्ट्ज, मॉर्गन स्टेनली के अध्यक्ष एवं सीईओ टेड पिक, वारबर्ग पिंग्स के अध्यक्ष चार्ल्स केय, एमनील

फार्मास्यूटिकल्स के सह-संस्थापक एवं सीईओ चिंटू पटेल तथा मास्टरकार्ड के सीईओ माइकल मीबाक के साथ अलग-अलग बैठकें कीं।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य भारत-अमेरिका व्यापार एवं निवेश संबंधों को मजबूत करना, भारत में

श्री गोयल ने भारत-अमेरिका रणनीतिक भागीदारी के सहयोग से आयोजित एक व्यावसायिक संवाद कार्यक्रम में निवेश और व्यापार समुदाय के 50 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों एवं व्यापारिक नेताओं को भी संबोधित किया। इस संवाद के दौरान भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, जारी आर्थिक सुधारों, कारोबार सुगमता, सहयोग की संभावनाओं वाले क्षेत्रों तथा विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में उभरते निवेश अवसरों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 681 अरब डॉलर पर

मुंबई, 29 मई. देश का विदेशी मुद्रा भंडार गत 22 मई को समाप्त सप्ताह में 7.511 अरब डॉलर घटकर 681.384 अरब डॉलर रह गया जो अप्रैल 2025 के बाद का निचला स्तर है।

विदेशी मुद्रा के देश के भंडार में लगातार दूसरे सप्ताह कमी आयी है। यह 15 मई को समाप्त सप्ताह में 8.096 अरब डॉलर घटकर 688.894 अरब डॉलर रहा था। रिजर्व बैंक द्वारा शुरुआत को जारी आंकड़ों के अनुसार, 22 मई को समाप्त सप्ताह में स्वर्ण भंडार 4.53 अरब डॉलर घटकर 114.786 अरब डॉलर हो गया। यह आठ सप्ताह में सबसे कम है।

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में आलोच्य सप्ताह में 2.872 अरब डॉलर की गिरावट रही। यह 22 मई को 543.032 अरब डॉलर रह गया।

अडानी समूह करेगा कच्छ आईटीआई सुधार

परियोजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य बनाना



भुज, 29 मई. अडानी समूह के प्रकल्प अडानी स्किल्स एंड एजुकेशन ने गुजरात सरकार के साथ मिल कर राज्य के कच्छ क्षेत्र के युवाओं के कौशल-आधारित करियर और कार्यबल विकास के उद्देश्य से 11 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सुधार करने की पहल की है।

अडानी समूह की ओर से शुरुआत को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस परियोजना के अंतर्गत आईटीआई संस्थानों का विकास इस प्रकार किया जाएगा कि स्थानीय रोजगार के नये अवसर पैदा हो सकें, रोजगार के

लिए पलायन कम हो तथा नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित कार्यबल विकसित हो सके। इस सहयोग के तहत पाठ्यक्रम उन्नयन, शिक्षक-प्रशिक्षक विकास, बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, व्यावहारिक

प्रशिक्षण और रोजगार के साथ साथ प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहां 'कर्म उत्सव' नाम से आयोजित कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की गयी। इस कार्यक्रम में 650 से अधिक छात्रों, शिक्षकों, नीति-निर्माताओं और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अडानी स्किल्स एंड एजुकेशन (एएसई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रॉबिन भोमिक के हवाले से बयान में कहा गया है कि कच्छ एएसई की दीर्घकालिक कौशल विकास दृष्टि का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने कहा, 'कच्छ हमारी कर्मभूमि है और हम इसके भविष्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।'

शेयर बाजार लुढ़के, सेंसेक्स 1,092 अंक टूटा

मुंबई, 29 मई. मौसम विभाग द्वारा इस साल मानसून के कमजोर रहने की भविष्यवाणी से घरेलू शेयर बाजारों में शुरुआत को गिरावट देखी गयी और बीएसई का सेंसेक्स लगभग 1,100 अंक टूट गया।

बढ़त में खुलने का बाद सेंसेक्स 1,092.06 अंक (1.44 प्रतिशत) लुढ़ककर 74,775.74 अंक पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 359.40 अंक यानी 1.5 प्रतिशत नीचे 23,547.75 अंक पर आ गया।

भारतीय मौसम विभाग ने आज सुबह बताया कि इस साल मानसून सीजन में दीर्घावधि औसत के 90 प्रतिशत के आसपास बारिश होने की उम्मीद

है, यानी मानसून औसत से कम रहेगा। कमजोर मानसून की चिंता में बाजार में बिकवाली शुरू हो गयी।

वृहत बाजार में भी गिरावट रही। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.49 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.85 प्रतिशत नीचे बंद हुआ।

आईटी (0.60 प्रतिशत की बढ़त) को छोड़कर सभी सेक्टरों के सूचकांक लाल निशान में रहे। तेल एवं गैस, धातु, ऑटो, बैंकिंग, वित्त, एफएमसीजी, फार्मा, स्वास्थ्य, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद और रसायन समूहों में बिकवाली ज्यादा देखी गयी।

सेंसेक्स की कंपनियों में पावर ग्रिड का शेयर करीब साढ़े तीन प्रतिशत लुढ़क गया।

आरबीआई रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था मजबूत

चालू खाता घाटा नियंत्रण में, घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र से मिला सहारा



नई दिल्ली, 29 मई। वैश्विक अनिश्चितताओं और आर्थिक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत लचीलापन दिखाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था स्थिर घरेलू मांग, तेजी से बढ़ते सेवा क्षेत्र और मजबूत निवेश गतिविधियों के चलते मजबूती के रास्ते पर बनी हुई है। रिपोर्ट में

जमा और ऋण दोनों में दोहरे अंकों की वृद्धि

रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग प्रणाली में भी सकारात्मक रुझान देखने को मिले हैं। जमा और ऋण दोनों में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है, जो यह दर्शाता है कि वित्तीय प्रणाली में तरलता और विश्वास दोनों मजबूत बने हुए हैं। वहीं, सरकार द्वारा राजकोषीय समेकन पर ध्यान देने और पूंजीगत व्यय बढ़ाने से भी आर्थिक गतिविधियों को गति मिली है। आरबीआई ने यह भी उल्लेख किया कि वित्तीय बाजारों ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। मुद्रा बाजार दरें नीतिगत रेषो दर और तरलता स्थितियों के अनुरूप बनी रही। ड्रिफ्टिंग बाजारों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जहां एक ओर नीतिगत समर्थन ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और एआई से जुड़ी अनिश्चितताओं ने दबाव भी बनाया।

स्पष्ट किया गया है कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत की आर्थिक बुनियादें मजबूत बनी रहीं, जिससे विकास की गति पर ज्यादा असर नहीं पड़ा।

आरबीआई ने कहा है कि चालू खाता घाटा (सीएडो) निर्धारित

निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी का कस

नई दिल्ली. ज्यादा मुनाफे और सुरक्षित निवेश का लालच देकर निवेशकों के साथ कथित धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। बंगलूरु पुलिस ने फिनटेक कंपनियों पर गंभीर आरोपों के चलते मामला दर्ज किया है। आरोप है कि 'मोबिविक्व एक्सट्रा' नामक निवेश योजना के जरिए देशभर के सैकड़ों निवेशकों के करोड़ों रुपये फंसा दिए गए और बाद में उन्हें अपने ही पैसे निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। पुलिस के अनुसार, यह मामला गुडगांव स्थित 'ट्रॉजेंकट्री टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड' और 'वन मोबिविक्व सिस्टम्स लिमिटेड' से जुड़ा है। शिकायतों में दावा किया गया है कि इन कंपनियों ने निवेशकों को यह भरोसा दिलाया कि यह योजना फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी सुरक्षित है।

अवसंरचना निवेश से लॉजिस्टिक्स लागत घटी

नयी दिल्ली, 29 मई. पिछले एक दशक में अवसंरचनाओं के विकास पर लगभग 360 अरब डॉलर खर्च किये गये हैं जिससे लॉजिस्टिक्स पर होने वाला खर्च घटकर जीडीपी के 10 प्रतिशत पर आ गया है।

उद्योग संगठन सीआईआई और नाइट फ्रैंक की शुरुआत को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक दशक में अवसंरचना विकास पर लगभग 360 अरब डॉलर का संचयी निवेश किया गया है। इसमें सार्वजनिक और निजी निवेश दोनों शामिल हैं। इससे लॉजिस्टिक्स लागत में भारी बचत

हुई है। सीआईआई मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट की इस साला रिपोर्ट के अनुसार, पहले देश की जीडीपी का 13-14 प्रतिशत लॉजिस्टिक्स पर खर्च होता था। अब यह आंकड़ा घटकर 10-10.7 प्रतिशत रह गया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को

हर साल 123-133 अरब डॉलर की बचत का अनुमान है। इसी का परिणाम है कि वैश्विक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) में भारत की रैंकिंग 2014 के 54वें स्थान से बढ़कर 2023 में 38वें स्थान पर पहुंच गयी है।

सोना-चांदी के दाम गिरे, बाजार में नरमी

नई दिल्ली, 29 मई। आज घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में दोनों कीमतें धातुएं लाल निशान में ट्रेड करती नजर आईं। सोने के दाम में करीब 700 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली, जबकि चांदी 1500 रुपये से अधिक सस्ती हो गई। इस गिरावट के चलते निवेशकों और संपर्ण कारोबारियों में हल्की सतर्कता का माहौल देखा जा रहा है।

ट्रेन में साइड लोअर सीट बुकिंग ट्रिक्स

नई दिल्ली, 29 मई। ट्रेन में यात्रा करते समय यात्रियों की सबसे पहली पसंद अक्सर साइड लोअर सीट होती है, क्योंकि यह सीट आरामदायक होती है और सफर को ज्यादा सुविधाजनक बनाती है। टिकट बुक करते समय सबसे जरूरी बात 'रिजर्वेशन चॉइस' का सही इस्तेमाल करना है। आईआरसीटीसी ऐप या वेबसाइट पर यात्री जब अपनी

जानकारी भरते हैं, तो वहां 'बर्थ प्रेफरेंस' का विकल्प आता है। इसमें साइड लोअर चुनने पर सिस्टम उसी सीट को देने की कोशिश करता है। इसके साथ ही अगर आप 'केवल वही टिकट बुक करें जब वही सीट मिले' वाला विकल्प चुनते हैं, तो टिकट तभी बुक होगा जब साइड लोअर सीट उपलब्ध होगी, जिससे बाद में परेशानी नहीं होती।

भारत एआई डिजिटल अर्थव्यवस्था में आगे

नई दिल्ली, 29 मई. भारतीय अंतरराष्ट्रीय संबंध अनुसंधान परिषद (इंक्रिएर) और पोरस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी की भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति पर केंद्रित इस वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की पाँचवीं सबसे अधिक डिजिटल इंडेक्स और चिप्स-एआई इंडेक्स में चौथे स्थान पर उभरा है।

शुरुआत को जारी 'स्टेट ऑफ इंडिया'स डिजिटल इकोनॉमी 2026' शीर्षक इस रिपोर्ट के अनुसार, 71 देशों को शामिल करने वाला यह व्यापक अध्ययन, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 96 प्रतिशत को कवर करता है, दर्शाता है कि भारत डिजिटल प्रदर्शन में जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकल रहा है। रिपोर्ट वैश्विक डिजिटल परिदृश्य में एक बड़े बदलाव को दर्शाती है। इसके अनुसार अब दुनिया के 72 प्रतिशत एआई उपयोगकर्ता विकासशील देशों में हैं, जिनमें भारत और चीन मिलकर वैश्विक एआई अपनाने का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं। जनरेटिव एआई इतिहास की किसी भी पूर्व तकनीक की तुलना में सबसे तेजी से फैलने



वाली तकनीक बन गई है और लॉन्च के तुरंत बाद ही यह विकासशील देशों में व्यापक रूप से अपनाई गई। वैश्विक डिजिटल नेतृत्व में भी बुनियादी बदलाव आ रहा है। दुनिया की शीर्ष पाँच डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से तीन — चीन, सिंगापुर और भारत — अब हिंद-प्रशांत क्षेत्र की हैं, जो पारंपरिक नॉर्थ अटलांटिक प्रभुत्व के साथ एक नए 'त्रिध्रुवीय डिजिटल व्यवस्था' के उभरने का संकेत देता है। इंक्रिएर के अध्यक्ष प्रमोद भसीन ने कहा, 'भारत ने कनेक्टिविटी, उद्यमिता और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से मजबूत नींव तैयार की है। विकास का अगला चरण इस बात पर निर्भर करेगा कि हम एआई का कितनी प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं।'

अत्याधुनिक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कुछ देशों तक सीमित है, हालाँकि एआई का उपयोग तेजी से फैल रहा है, लेकिन उन्नत चिप्स, कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े भाषा मॉडल अभी भी सीमित देशों और कंपनियों के नियंत्रण में हैं। बड़े पैमाने पर एआई के इस्तेमाल को नवाचार में बदलना भारत की सबसे बड़ी चुनौती है।

समाचार विशेष

उपमुख्यमंत्री के किले में भाजपा समर्थित की संधमारी



कार्यकर्ताओं को मेहनत की जीत बताया है। लखबीर सिंह लक्खी पहले भी जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा वह भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के मंडल संयोजक भी जिम्मेदारी भी निभा रहे। वह लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का दावा है कि यह परिणाम बताता है कि केवल बड़े विकास के दावे या सरकारी पद का प्रभाव ही चुनाव नहीं जिताता, बल्कि जमीनी संपर्क और स्थानीय मुद्दों की समझ ज्यादा महत्वपूर्ण होती।

उपमुख्यमंत्री के लिए बड़ी राजनीतिक चोट- राजनीतिक जानकारों के अनुसार यह हार इसलिए अधिक चर्चा में है, क्योंकि चुनाव उपमुख्यमंत्री की गृह पंचायत में हुआ। जिस क्षेत्र को उनका राजनीतिक किला माना जाता था, वहीं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ समय से उपमुख्यमंत्री का पूरा फोकस हरोली विधानसभा क्षेत्र में बढलते राजनीतिक समीकरणों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा खेमे ने इस जीत को संगठन की मजबूती और

कार्यकर्ताओं को मेहनत की जीत बताया है। लखबीर सिंह लक्खी पहले भी जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा वह भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के मंडल संयोजक भी जिम्मेदारी भी निभा रहे। वह लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का दावा है कि यह परिणाम बताता है कि केवल बड़े विकास के दावे या सरकारी पद का प्रभाव ही चुनाव नहीं जिताता, बल्कि जमीनी संपर्क और स्थानीय मुद्दों की समझ ज्यादा महत्वपूर्ण होती।

उपमुख्यमंत्री के लिए बड़ी राजनीतिक चोट- राजनीतिक जानकारों के अनुसार यह हार इसलिए अधिक चर्चा में है, क्योंकि चुनाव उपमुख्यमंत्री की गृह पंचायत में हुआ। जिस क्षेत्र को उनका राजनीतिक किला माना जाता था, वहीं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ समय से उपमुख्यमंत्री का पूरा फोकस हरोली विधानसभा क्षेत्र में बढलते राजनीतिक समीकरणों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा खेमे ने इस जीत को संगठन की मजबूती और

राज्यसभा चुनाव : बीजेपी खेलेगी 'महिला कार्ड' ?



जयपुर. राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में सियासी चौरसर बिछने लगी है। राज्यसभा में राजस्थान के कोटे की तीन सीटों 18 जून को खाली हो रही हैं। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के सदस्यों की संख्या को देखते हुए इन तीन सीटों में से दो बीजेपी के और एक कांग्रेस में पाले में जाने के आसार हैं।

अब तक केवल 9 महिलाएं ही उच्च सदन तक पहुंच सकीं। इसको लेकर अभी तक दोनों ही पार्टियों ने अपने पते नहीं खोले हैं। राजस्थान से अब तक राज्यसभा में पहुंचे सदस्यों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। महिला प्रतिनिधित्व हमेशा सीमित रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी के 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला वोट बैंक और राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की चर्चाओं ने राजस्थान की तीन सीटों के चुनाव को दिलचस्प बनाने की ओर कदम बढ़ा दिये हैं। इस बार संभवतः समीकरण बदल दिए जाएं। देशभर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने भाजपा

पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश की दो सीटों कोटे के गणित के आधार पर भाजपा के खाते में जाने वाली है तो दोनों पर महिलाओं को भेजा जाना चाहिये, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती हैं। लेकिन केवल बातें करने से काम नहीं चलने वाला है। अब देखते हैं कि वह महिलाओं को राज्यसभा चुनाव में कितना अवसर देती है। भाजपा अगर राज्यसभा चुनाव के दंगल में महिला उम्मीदवार उतारती है तो यह केवल राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि प्रतीकात्मक संदेश भी होगा।

कांग्रेस भी कर रही है गंभीरता से विचार भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में महिला मोर्चा से जुड़ी नेताओं को राज्यसभा भेजा है। इससे राजस्थान में भी महिला उम्मीदवार की संभावना और मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन किसे भेजा जाएगा इस पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में भी ऐसा ही चल रहा है। वहां भी महिला उम्मीदवार को लेकर सरगमियां तेज हैं। कांग्रेस भी इस बार महिला उम्मीदवार उतारने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

दोनों उपचुनाव दिलचस्प हैं

नई दिल्ली. महाराष्ट्र और तमिलनाडु दो राज्यों में राज्यसभा की दो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार के इस्तीफे से सीट खाली हुई है। वे अपने पति अजित पवार के निधन के बाद उप मुख्यमंत्री बनीं और उनकी खाली हुई बरामती सीट से विधायक हो गई हैं।

उधर तमिलनाडु में अन्ना डीएमके नेता सीवी घणुमगम भी विधायक बन गए हैं। उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट पर उपचुनाव होगा। ऐसा लग रहा है कि नई बनी पार्टी टीवीके का खाता अभी तुरंत खुल जाएगा। गौरतलब है कि दो साल पहले बनी पार्टी टीवीके 107 सीट जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बनी

कांग्रेस संगठन में बढ़ सकती है अंदरूनी बेचैनी

इस हार के बाद कांग्रेस समर्थकों में निराशा साफ दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर भी यह चर्चा शुरू हो गई है कि स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक तालमेल कमजोर पड़ा है। हरोली विधानसभा क्षेत्र लंबे समय से मुकेश अग्निहोत्री का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। यहां से मुकेश अग्निहोत्री लगातार पांचवीं बार विधायक बनने के बाद प्रदेश के पहले उपमुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन भाजपा की यह जीत संकेत दे रही है कि पार्टी अब स्थानीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है।

इस हार के बाद कांग्रेस समर्थकों में निराशा साफ दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर भी यह चर्चा शुरू हो गई है कि स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक तालमेल कमजोर पड़ा है। हरोली विधानसभा क्षेत्र लंबे समय से मुकेश अग्निहोत्री का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। यहां से मुकेश अग्निहोत्री लगातार पांचवीं बार विधायक बनने के बाद प्रदेश के पहले उपमुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन भाजपा की यह जीत संकेत दे रही है कि पार्टी अब स्थानीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है।

विशेष सप्ता में लौटने का योगी का फॉर्मूला, संघ चीफ के दौरे से हलचल तेज



लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने है, लेकिन इसके पहले ही प्रदेश में राजनीति माहौल गर्म होना शुरू हो गया है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत तीन दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आए हुए थे। जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके साथ ही उन्होंने संघ के उच्च अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री माहौल गर्म होना शुरू हो गया है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत तीन दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आए हुए थे। जहां

क्या है संघ का ट्रिपल एस मॉडल ?

चुके हैं और तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। हालांकि, संघ ने इसे सामान्य संगठनात्मक कार्यक्रम और शताब्दी वर्ष की समीक्षा बताया, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे आने वाले चुनावों की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। मोहन भागवत का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी 2027 में लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भाजपा और संघ के बीच तालमेल को और मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए 'ट्रिपल एस मॉडल' को सबसे अहम रणनीति माना जा रहा है।

ट्रिपल एस मॉडल का मतलब है संघ, संगठन और सरकार के बीच मजबूत तालमेल बनाना। इसके तहत संघ वैचारिक ताकत और अनुशासित कार्यकर्ताओं का नेटवर्क उपलब्ध कराएगा। वहीं, संगठन यानी भाजपा चुनावी रणनीति तैयार करने से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का काम करेगी। जबकि सरकार अपने कामकाज और योजनाओं के जरिए जनता के बीच अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम करेगी। माना जाता है कि जब ये तीनों साथ मिलकर एक दिशा में करना शुरू सकते हैं तो भाजपा की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। पिछले कई चुनावों में इस मॉडल का असर देखने को मिला है।

सीएम योगी समेत बड़े नेताओं से मुलाकात

अपने इस दौरे के दौरान मोहन भागवत ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक समेत भाजपा के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाना माना जा रहा है। संघ लंबे समय से भाजपा को जमीनी फीडबैक देता आ रहा है। यह ऐसा फीडबैक होता है जो अक्सर सरकारी अधिकारियों के जरिए ऊपर तक नहीं पहुंच पाता।